<u>राज्य सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *94

27 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग पर ऋण का बोझ

***94. श्री मनीष गुप्ताः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग पर ऋण का भारी बोझ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कच्चे माल की लागत, विद्युत लागत तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण उत्पादन और मांग में कमी आ रही है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या उपाय प्रारंभ किए जा रहे हैं;

(ग) क्या वर्ष 2030-31 तक लगभग 300 मिलियन टन की उच्च इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के मामले में प्रगति हो रही है जबकि वर्तमान क्षमता 100 मिलियन टन से कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“इस्पात उद्योग पर ऋण का बोझ” के बारे में श्री मनीष गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 27 नवंबर, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *94 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी नहीं। इस्पात एक पूँजीप्रधान उद्योग है और इसमें प्रतिफल प्राप्त होने की अवधि काफी लंबी होती है। इस्पात कंपनियों को क्षमता विस्तारण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन जैसी गतिविधियों के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। विद्युत और इस्पात जैसे पूँजीप्रधान और लंबी प्रतिफलन अवधि वाले क्षेत्रों हेतु आदर्श ऋण इक्विटी अनुपात 2:1 है। वर्तमान में भारतीय इस्पात क्षेत्र में ऋण इक्विटी अनुपात 2:1 से कम है।

(ख): जी नहीं।

(ग) और (घ): जी हाँ। स्वदेशी क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता वर्ष 2014-15 के 109.85 एमटी से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 142.24 एमटी हो गई है। इसके साथ लगभग 28 एमटीपीए तक क्षमता संवर्द्धन का कार्य भी चल रहा है।

****